



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1987/फाल्गुन 22, 1908

No 114]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1987/PHALGUNA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

राज्य विभाग

(विदेश पर प्रभाग)

नई दिल्ली 13 मार्च 1987

अधिसूचना

सायबर

सा का नि 282(अ) — यह भारत के गणराज्य की सरकार तथा
हंगरी लोक गणराज्य की सरकार — बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे
कराधान के परिहार के लिए गतवर्ष अधिसूचना, उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद
28 के अनुसरण में दोनों सविशेषकारी राज्यों द्वारा उक्त लागू किए जाने
के लिए उक्त कानून द्वारा यथापेक्षित कार्यविधियां केंद्रित करने के बारे में
एक-दूसरे को अधिसूचित किये जाने पर दिनांक 7 जनवरी, 1987 को
प्रवृत्त हो गया है,

अतः अब, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा
90 तथा कम्पनी (लाभ) अधिनियम 1961 (1964 का 7)
की धारा 24 ग द्वारा पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, केन्द्रिय सरकार
एतद्वारा निवेदन करती है कि उक्त अधिसूचना के सभी उपबन्धों का भारत
संघ में लागू किया जाएगा।

अनुबन्ध

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए
भारत गणराज्य की सरकार और हंगरी लोक गणराज्य की सरकार के बीच
अधिसूचना।

भारत गणराज्य की सरकार और हंगरी लोक गणराज्य की सरकार
पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों का और आगे विस्तार करने तथा उन्हें
सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से व्यापक करों के दोहरे कराधान के
परिहार के लिए अधिसूचना निम्नांकित करने हेतु निम्नानुसार सहमत हुई
है —

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत विषय-शेष

यह अधिसूचना उन व्यक्तियों पर लागू होगी, जो दोनों सविशेषकारी
राज्यों में से किसी एक प्रत्येक दोनों राज्यों में निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले कर

1 यह अधिसूचना प्रत्येक सविशेषकारी राज्य प्रत्येक उनके राजनैतिक
उप-प्रभाग प्रत्येक स्थानीय पाठ्यालयों से और से आप पर लगाये गए
करों के आसानी से लागू होगा खाते के कर जिनो से कर से उगाए जाने
हों।

2 यह अधिसूचना जिन करों पर लागू होगा वे हैं —

(क) भारत के सम्बन्ध में

(1) सायबर जिन पर आप पर उक्त अधिसूचना की धारा अधिसूचना
शामिल है

(2) धनिक

(जिन्हें एतद्वत्त्वात् "भारतीय कर" कहा गया है।)

(ख) हंगरी लोक-गणराज्य के मामले में :

- (1) सामान्य आय-कर (एज ए "एस्टाब्लिशमेंट जे"; बेडेलेमा ओ);
- (2) गृह-सम्पत्ति तथा अनुषंगी फार्मों पर आयकर (ए एज एजता जी एन किसेगी टिड गजडासा गौक जो बेडेलेमाओ जा);
- (3) निगम कर (ए तरमलेटी ए ओ ए ए तरसाजी ए ओ);
- (4) विशेष निगम कर (ए तरसलेटी कोनोनाओ);
- (5) सरकारी उद्यमों का लाभकर (एज एलेसी बेलेसटोक नियरे सोगाडासा);
- (6) शहरी तथा सामुदायिक अश्वान (बरोमी एस कोजसेगी होजाजसलास);

(7) वाणिज्यिक कम्पनियों के लाभांशों तथा लाभ वितरणों पर कर (ए को रैसकेड तरमासागौक ओम नियरेसेज किफिजेलेसी उत्तानी इलेटेक);

(जिन्हें एतद्वत्त्वात् "हंगरी कर" कहा गया है।)

3 यह अभिसमय किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से एक-समान करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैरा 2 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके रवान पर वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लागू जाएंगे।

4. प्रत्येक वर्ष के अन्त में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने उन कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे, जो इस अभिसमय के विषय हैं तथा सम्बन्धित कानूनों और विनियमों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस अभिसमय के उद्देश्य के लिए, जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

- (क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है, भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का आकाशीय क्षेत्र और इसके साथ ही साथ इसमें वह अन्य कोई समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, भारत के प्रभुत्वता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं;
- (ख) "हंगरी लोक-गणराज्य" शब्द से अभिप्रेत है हंगरी लोक-गणराज्य का राज्यक्षेत्र;
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से अभिप्राय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत गणराज्य अथवा हंगरी लोक-गणराज्य अभिप्रेत हैं;
- (घ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी तथा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है;
- (ङ) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है, जो कर के प्रयोजनार्थ एक निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;
- (च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(छ) किसी संविदाकारी राज्य के "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है :-

- (1) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त कोई भी व्यक्ति;
- (ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा मस्था, जो किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों में इस प्रकार की अपनी हैसियत रखता है,

(ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायान" शब्दों का अभिप्राय किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा किसी परिवहन से है, जिसका संचालन कोई ऐसा उद्यम करता हो, जिसकी किसी संविदाकारी राज्य में अपनी प्रभावी प्रबन्ध-व्यवस्था हो; सिवाए इसके कि जब उक्त जलयान अथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(झ) भारत के मामले में "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग); तथा हंगरी लोक गणराज्य के मामले में अभिप्रेत है—वित्त मंत्रालय

2. जहाँ तक दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के उपबन्धों को लागू किए जाने का सम्बन्ध है, किसी शब्द का, जो इसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वह अर्थ होगा, जो उस राज्य में कानूनी से सम्बन्धित प्रवृत्त कानूनों के प्रयोजनार्थ हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 4

प्राथमिक अधिवास

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से अभिप्रेत है—ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा इससे मिलती-जुलती किसी अन्य कसौटी के कारण, उस राज्य में कर लगाया जाना अपेक्षित हो।

2 जहाँ इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी :-

- (क) वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास कोई स्थायी गृह उपलब्ध हो। यदि उसके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र स्थित है;
- (ख) उस संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र स्थित है, निर्णय नहीं किया जा सकता हो अथवा उनके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में से किना भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका कोई व्यावहारिक आवास हो;
- (ग) यदि उसका व्यावहारिक आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है नां संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से अनुच्छेद 25 के अनुसार इस प्रश्न का निर्धारण करेंगे।

3. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारणों से, किसी व्यक्ति से निम्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस

संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उनकी प्रभावी प्रवर्ध-व्यवस्था का स्थापन स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अधिसूचक के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारोबार अथवा उत्पादन का वह कोई निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ से किसी उद्यम के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा अंशतः चलाए जाते हैं।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(क) प्रबन्ध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कर्मशाला अथवा कोई भांडारखाने ;

(च) कोई खान, कोई खदान, कोई तेल क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रतिष्ठान अथवा ऐम्प्लोयी परियोजना अथवा इनके सम्बन्ध पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलाप जहाँ ऐसे स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलाप 6 महीनों से अधिक समय तक चलते रहते हैं अथवा जहाँ ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलाप मशीनरी अथवा उपकरणों की बिक्री के कारण आकस्मिक किस्म के होते हैं और 6 महीनों में अधिक समय तक जहाँ चलते हैं तथा उन परियोजना अथवा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलापों के लिए देय प्रभार उक्त मशीनरी तथा उपकरणों के बिक्री-मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

3. इन अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपाधियों के होने हुए भी, "स्थायी संस्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

(क) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का उपयोग ;

(ख) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टोक के मात्र संचारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;

(ग) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टोक का किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किये जाने मात्र के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;

(घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का काम करने अथवा उनके बारे में सूचना संग्रहीत करने के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव ;

(ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के किसी अन्य कार्यकलाप के संचालन के प्रयोजनार्थ अनन्य रूप से कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव ;

(च) उप-पैरा (क) से (ङ) में उल्लिखित किसी भी कार्यकलाप के संयोजन के लिए अनन्य रूप से कारोबार के किसी भी निश्चित स्थान का रख-रखाव, बशर्तकि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के उक्त निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा अनुसंधानी किस्म के हों।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद जहाँ कोई व्यक्ति, जो किसी स्वतंत्र हेतियत के किसी अभिक्रमा में मिला हो और जिस पर पैराग्राफ 5 की व्यवस्थाएँ लागू होती हैं - एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो ऐसे मामले में, किसी भी प्रकार के कार्यकलापों को, जिन्हें वह व्यक्ति उस

उद्यम के लिए कर रहा हो, उस उद्यम का प्रयोजक राज्य में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि वह व्यक्ति -

(क) उक्त राज्य में उस उद्यम के नाम से संविदाएँ निष्पन्न करने का प्राधिकार रखता हो तथा व्यवहारिक रूप से ऐसे प्राधिकार का उपयोग करता हो, बशर्तकि ऐसे व्यक्ति के कारोबार पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कार्यकलापों पर हो सीमित हों, जब तक कि वे कार्यकलाप कारोबार के किसी निश्चित स्थान के माध्यम से किए गए हों, उदाहरण के तत्परता के अन्तर्गत कारोबार का निश्चित स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बल्कि, अथवा

(ख) उसे ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है लेकिन प्रयोजक राज्य में व्यावहारिक रूप से मान अथवा पण्य-वस्तुओं का एक ऐसा स्टोक रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम की ओर से मान अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिप्रीवरी करता रहा है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन का स्थित होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी बलात्, सामान्य कमिशन एजेंट अथवा एक स्वतंत्र हेतियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति या कारोबार के काम संचालन का से कर रहे हो। किन्तु, जब इस प्रकार के एजेंट के कारोबार उस उद्यम की ओर से पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से किए जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हेतियत का एजेंट नहीं माना जाएगा।

6. इस तथ्य से कोई कर्तवी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण करने है अथवा जो किसी ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित है जो उस दूसरे राज्य का निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार चलाती है, उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगा।

अनुच्छेद 6

अवन संपत्ति से प्राप्त

1. अवन संपत्ति से प्राप्त प्राप्त पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिस राज्य में ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. "अवन संपत्ति" शब्दों की परिभाषा आगे दिये गए राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत की जाएगी, जिनमें यह संपत्ति स्थित है। इन राज्यों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अवन संपत्ति के उप-प्राप्त के रूप में संपत्ति, कृषि और शाली में प्रयुक्त पशुधन तथा उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर संविदाकारी राज्यों के संपत्ति संबंधी सामान्य कानूनों के द्वारा लागू होते हैं, अवन संपत्ति का भाड़े के प्रतिफल तथा अविश्व भंडारों, तेल के कुप्पा, खदानों तथा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के अथवा स्थायी के संचालन अथवा संचालन-प्राधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत भुगतानों का प्रतिफल। जहाजों, नौकायां तथा वायुयानों को अवन संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत, अवन संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग में होने वाली आय पर लागू होगी।

4. पैराग्राफ (1) और (3) के अन्तर्गत किसी उद्यम को अवन संपत्ति से प्राप्त प्राप्त का मायनार्थ व्यावहारिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में लाने गई अवन संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होगी।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में

वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि वह उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा, जिनके लिए उन्तरवादी कारण केवल इस प्रकार हो सकते हैं— (क) वह स्थायी संस्थापन (घ) उस दूसरे राज्य में उसी प्रकार के अथवा अपने-जैसे माने अथवा पथ-वस्तुओं की बिन्नी जैसे कि उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेंचे जाते हैं, अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में किन्हीं-उसी प्रकार के अथवा उससे मिलते-जुलते व्यावसायिक कार्य-कलाप जैसे उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हैं।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक सविदाकारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसे उन लाभों का उत्पन्न होता माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की उसे तब अपेक्षा रहती, जब वह समरूप अथवा उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों के अंतर्गत समरूप अथवा एक-समान कार्यकलाप में लगा हुआ एक निश्चित तथा अलग उद्यम होता और जिस उद्यम का वह एक स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से व्यापार करता होता।

3. जहाँ किसी सविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुछ लाभों को उसके विभिन्न भागों के प्रति एक अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न लाभों का उद्य करने की कोई प्रथा हो, वहाँ पैराग्राफ (2) की कोई भी व्याख्या उस सविदाकारी राज्य को ऐसे परस्पर गत अनुभाजन पद्धति से, कराघेय लाभों के तब करने से नहीं राकेगी तथापि वह अनुभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित विधानों के अनुसार होगा।

4. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में व्यव की रकमा की कटौतियों की स्वीकृति उक्त राज्य के कराघन कानूनों के उपबन्धों के अनुरूप तथा उनकी सीमाओं के भीतर रहते हुए दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए व्यव की गई हो जिसमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों, जहाँ उक्त स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र स्थित है। तथापि, उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय का अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय का पेटेंटों, तकनीकी की जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीस अथवा इनसे मिलती-जुलती अन्य अवायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा-सम्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रकार के रूप में अथवा किसी भी उद्यम के मामले की ठाड़कर स्थायी संस्थापन को उधार दिये गए धन पर ब्याज के रूप में, अदा की गई रकमे यदि कोई हो (वास्तविक व्यव की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों की हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्वयं संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय का पेटेंटों, तकनीकी जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीस अथवा इनसे मिलती-जुलती अन्य अवायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा-सम्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रकार के रूप में अथवा किसी भी उद्यम के मामले का छोड़कर प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप (वास्तविक व्यव की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) में प्रभावित की गई हो।

5. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन का हूए, नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा निर्यात के उद्देश्य से उस उद्यम के लिए गान अथवा पथ-वस्तुएं खरादी गई हैं, जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों की तब तक उन्नी पद्धति में अर्थात् निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि उनके विरुद्ध कोई उद्युक्त तथा पारित कारण नहीं हो।

7. जहाँ लाभों में आय की वे सवें भी शामिल हों, जिनका विवेचन इस अधिसूचना के अन्य अनुच्छेदों में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों में उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

वायु परिवहन

1. दोनों सविदाकारी राज्यों में से किसी एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से प्राप्त आय पर दूसरे सविदाकारी राज्य में कर नहीं लगेगा।

2. इसी तरह वायु-परिवहन के कार्यों में लगे उद्यमों के पूरा में किसी भी प्रकार की भागीदारी के सम्बन्ध में पैराग्राफ 1 लागू होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में भी लागू होंगे जहाँ उद्यम का दूसरे राज्य में माल अथवा व्यक्तियों के परिवहन के लिए कोई कार्यालय अथवा अधिकरण है। तथापि, यह केवल वायुयान परिवहन के कारोबार में सीधे संबंधित कार्यकलापों पर ही लागू होगा।

4. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान के संचालन, जैसा कि पैरा 1 में उल्लेख किया गया है, से संबंधित निधि पर ब्याज को इस प्रकार के वायुयान के संचालन से प्राप्त आय समझा जाएगा।

अनुच्छेद 9

संबन्ध उद्यम

जहाँ.—

(क) एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में किसी उद्यम की प्रबन्ध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्ष भाग लेता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में प्रबन्ध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी में भाग लेते हैं, और दोनों में से किसी भी प्रवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी जाती हैं अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, ऐसे मामलों में ऐसे कोई लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की हालत में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किए जाएंगे और वे तदनुसार कराघेय होंगे।

2. जहाँ एक सविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम उस दूसरे राज्य में कर लगाता है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ वे लाभ हैं, जो प्रथमोक्त राज्य के उक्त उद्यम को प्राप्त हुए होते, यदि दो उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें वे होतीं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई जाती हैं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर वही प्रभावित कर को गणित का समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन का विनिश्चय कथन में, इस अधिसूचना के अन्य उपबन्धों का भी संदर्भ रखा गया और यदि आवश्यक हो तो, सविदाकारी राज्यों के सहाय प्राधिकारों एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1 जो कम्पनी एक सविदाकारी राज्य की निवासी हो उसके द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अथवा किए गए लाभों में उस राज्य में कराधेय होंगे।

2 तथापि इस प्रकार के लाभों में उस सविदाकारी राज्य में जो कराधेय होंगे, जिसकी लाभांश अर्थात् करने वाली कम्पनी उक्त राज्य के कानूनों के अनुसार निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभों का लाभ भोगी स्वामी है और लाभांश किसी नए अवदान से संबंधित है तो इस प्रकार प्रसारित कर की राशि लाभांश की कुल रकम से पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि लाभभागी स्वामी एक ऐसी कम्पनी है जो लाभांश प्राप्त करने वाली कम्पनी में कम-से-कम 10 प्रतिशत शेयर रखती है।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के बारे में कम्पनी के मरणांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों की अदायगी की जाती है।

3 इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त 'लाभांश' शब्द का अभिप्राय ऐसे शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो ऋण, बंधे नहीं हैं और लाभों के गृहभागी हैं, तथा इनके साथ साथ अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर उस सविदाकारी राज्य के उन्हीं कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है जिसकी विवरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का प्राप्तकर्ता स्वयं, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसका लाभांश अर्थात् करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उक्त दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान में प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

5 जहां कोई कम्पनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां उस कम्पनी द्वारा अर्थात् किए गए लाभों पर, जहां तक कि ऐसे लाभों को छोड़कर, जो उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अर्थात् किए गए हों अथवा जहां तक कि ऐसी धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान में प्रभावी रूप से सम्बन्धित है उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभ कर की किसी कर लगाया जाएगा, चूंकि अर्थात् किए गए लाभों अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हैं।

6 जैसा कि इस अनुच्छेद के पैरा 2 में प्रदाय किया गया है नए अवदान शब्दों से अभिप्राय कोई भी शेयर पत्रों जो वित्त शेयरों अथवा वा अथवा उससे अधिक विद्यमान कम्पनियों में समामलन के परिणामस्वरूप गठित की गई किसी नई कम्पनी के शेयरों से भिन्न हों, और जो इस अधिसूचक के प्रवृत्त होने के तारीख के पश्चात् उस कम्पनी द्वारा जारी किए गए हों जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है और दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासी के लाभभागी स्वामित्व में है।

अनुच्छेद 11

व्याज

1 एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी का अर्थात् किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2 तथापि इस प्रकार के व्याज पर उस सविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा जिस राज्य में यह उद्भूत

होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी हो तथा व्याज की अदायगी इस अधिसूचक के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् पड़े तो उत्पन्न हुए ऋण अथवा उधार के सम्बन्ध में की गई हो तो इस प्रकार प्रसारित कर की राशि व्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3 पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अन्तर्गत —

(क) एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज पर उस राज्य में कर में छूट प्राप्त होगी यदि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा लाभ-धारित हो

(1) दूसरे सविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा

(II) दूसरे सविदाकारी राज्य का संप्रदायिक बैंक,

(ख) किसी सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए व्याज पर उक्त राज्य में कर में छूट होगी यदि वह दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी के लाभभागी स्वामित्व में हो और निम्नलिखित द्वारा दिए गए अथवा सममित ऋण अथवा उधार के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया हो

(1) इसरी लोक गणराज्य के मामले में माग्यार कुम्करेस-बन्धना बैंक और टी उमहद तक जहां तक ऐसा व्याज कर्षण नियमित तथा आयात के वित्त-पोषण के कारण हुआ हो,

(II) भारत के मामले में भारत का आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम् बैंक) उस तब तक, जहां तक ऐसा व्याज केवल आयात और निर्यात के वित्त पोषण के कारण हुआ हो,

(III) आयात-व्यापार के लोक-वित्त पोषण के प्रभावी सविदाकारी राज्य का कोई भी संस्थान,

(IV) कोई भी अन्य व्यक्ति बशर्ते कि ऋण अथवा उधार प्रथमावक सविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

4 इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त 'व्याज' शब्द का अभिप्राय सभी प्रकार के ऋण-दायों से प्राप्त आय से है, चाहे वह ऋण-दायों के रूप में प्रारम्भित रखी गई हो अथवा नहीं रखी गई हो और चाहे उनमें बंधन के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं प्राप्त हो, और विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली आय और बन्धन-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त होने वाली आय में जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्धन-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों के साथ जुड़े हुए लाभ तथा पुरस्कार से प्राप्त आय भी शामिल है। पैरा में की गई अदायगी के लिए लगाए गए अर्थदंड का इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ व्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी एक सविदाकारी राज्य का निवासी हो तो कारण दूसरे सविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाना हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान में स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करना हो और जिस ऋण-दायों के बारे में व्याज अर्थात् किया जाता हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो लागू होंगे।

6 किसी सविदाकारी राज्य में उस स्थिति में व्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि व्याज अर्थात् करने वाला स्वयं वह सविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उक्त राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहां व्याज अर्थात् करने वाले व्यक्ति का कोई भी किसी सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है अथवा नियत स्थान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था और जिस पर व्याज की अदायगी की गई थी और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन

अथवा नियत स्थान द्वारा बहन किया जाता है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित हो।

7. जहाँ व्याज भ्रष्ट करने वाले तथा लाभ-भोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों में तथा और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण, व्याज की रकम उस ऋण दावे की ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए व्याज की रकम भ्रष्ट की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध के नहीं होने की स्थिति में व्याज भ्रष्ट करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हुई थी, तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। इस प्रकार के मामले में अदायगी के अनिश्चित भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 12

रायल्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए उद्भूत हुई फीस पर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को भ्रष्ट की गई हो, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. लेकिन, उस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा जिस राज्य में ये उद्भूत हुई हों बशर्ते कि ये रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को भ्रष्ट की गई हों, जो इनका लाभभोगी स्वामी हो और जो अधिकार अथवा सम्पत्ति के सबंध में भ्रष्ट की गई हो, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात् प्रथमतः प्रदान की गई हो अथवा हस्ताक्षरित करार के अधीन दी गई हों। इस प्रकार प्रभावित किया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए।

- (क) रायल्टियों के मामले में, सकल राशि का 40 प्रतिशत,
- (ख) तकनीकी सेवाओं के लिये फीस के मामले में एकल राशि का 20 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से निम्नलिखित के लिये प्रतिकूल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की अदायगियां, जिसमें किराया भी शामिल है, अभिप्रेत हैं—

- (क) साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृतियों जितने रेडियों अथवा दूरदर्शन से प्रसारण के लिये प्रयुक्त की जाने वाली चलचित्र फिल्मों तथा फिल्मों अथवा टेपे शामिल हैं के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिये,
- (ख) किमी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा साधन, प्लान गुप्त फार्मूला अथवा अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिये,
- (ग) औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित जानकारी के लिये।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिये फीस" पद से प्रत्यक्षीय, तकनीकी अथवा परामर्शदायी स्वरूप की सेवाओं के लिये प्रतिकूल के रूप में, जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कामियों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को और अनुच्छेद 14 (स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं) में उल्लिखित स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाओं के लिये किसी व्यक्ति को की गई अदायगियों से भिन्न, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रकम की अदायगियां अभिप्रेत हैं।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस उद्भूत होती है या वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करना है और जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के सम्बन्ध में रायल्टियां या तकनीकी सेवाओं के लिये फीस भ्रष्ट की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 (व्यावसायिक लाभ) अथवा अनुच्छेद 14 (स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं) के उपबन्ध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. रायल्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी जब भ्रष्ट करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहां रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस भ्रष्ट करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके सम्बन्ध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस की अदायगी का दायित्व उपगत था और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा बहन की जाती है तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदायगी और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस की रकम, जो ऐसे सम्बन्ध न होने पर भ्रष्ट की गई होती उस रकम से किसी भी कारण से बढ़ जाती है तो वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। उस मामले में अधिक भ्रष्ट की गई रकम पर इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों पर योजित ध्यान देते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 13

पूँजीगत अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अनुच्छेद 6 में उल्लिखित तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित प्रचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त हुए अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से सम्बन्धित चल सम्पत्ति हो, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अर्केल) अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से प्राप्त होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय, यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों जैसी पूँजीगत परिसम्पत्ति में अथवा ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के मचालन से संबन्धित चल सम्पत्ति से उद्भूत होने वाले अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उक्त उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा

अप्रत्यक्षतः प्रदानतया किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अल्पसंख्यक हो, उसी राज्य में कर लगेगा।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3, तथा 4 में उल्लिखित सम्पत्ति में भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त होने वाले अभिलाषी पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका कि अन्तरकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद 14

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं

1 किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, स्वतन्त्र हैसियत में व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि ऐसी सेवायें दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित नहीं की जाती हैं, ऐसे मामले में ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदि

(क) वह व्यक्ति "विगत वर्ष" अथवा "करायेय वर्ष" में ग्रेपी भी स्थिति हो, उस दूसरे राज्य में कुल मिलाकर 90 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिये मौजूद रहा हो; अथवा

(ख) उस व्यक्ति को अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य कोई निश्चित स्थान नियमित रूप में उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में आय की उतनी रकम पर कर लगेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है।

2. "स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं" पद में स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अस्पृश्य सम्बन्धी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, स्वास्थ्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दल-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतन्त्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराश्रित व्यक्तिगत सेवायें

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 के उपबन्धों के अन्वये रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के मन्त्र में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता है। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्नखित राज्य में ही कर लगेगा, यदि:

(क) पारिश्रमिक प्राप्तकर्ता संगत "विगत वर्ष" अथवा "करायेय वर्ष" में, ग्रेपी स्थिति हो, कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक अवधि अथवा अवधियों के लिये दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो; तथा

(ख) पारिश्रमिक की अदायगी किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की जाती है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; तथा

(ग) पारिश्रमिक को किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जोकि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिवहित जलयान अथवा वायुयान पर किये गये किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त

पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 16

निदेशक की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा पर्यवेक्षी बोर्ड अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य संगठन के एक सदस्य की हैसियत से, जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उससे मिलती-जुलती किस्म की अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 तथा 15 के उपबन्धों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्ताओं (जैसे कि किसी थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकरों तथा संगीतकारों) अथवा खिलाड़ियों द्वारा अपने इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिसमें कि ये कार्यकलाप किये जाते हैं।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किये गये व्यक्तिगत कार्यकलापों के सम्बन्ध में आय स्वयं मनोरंजन कर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो, ऐसे मामले में उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपबन्धों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते हैं।

3 इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, ऐसे कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी जिसमें ऐसे कार्यकलाप किये जाते हैं, यदि लोक मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलाड़ियों के उस राज्य के बोरे के खर्चों को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार की लोक निधियों से पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से पूरा किया जाना हो।

4 इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये "सरकार" शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य सरकार, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण शामिल है।

अनुच्छेद 18

पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अन्वये रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके विगत नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन तथा उसमें मिलते-जुलते अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में लगेगा।

2 पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, प्रत्येक पेंशन तथा किसी सार्वजनिक योजना के अन्तर्गत की गई अन्य अदायगियां, जोकि एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक भाग है, केवल उस राज्य में करायेय होगी।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा

1. भारतीय गणराज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को, जो भारत का एक नागरिक है, हंगरी लोक गणराज्य में सरकारी कामकाज के निष्पादन में की गई सेवाओं के मन्त्र में प्रदत्त पारिश्रमिक (जो पेंशन नहीं है) को हंगरी के कर में छूट प्राप्त होगी।

2. हंगरी लोक गणराज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को, जो हंगरी लोक गणराज्य का एक नागरिक है, भारत में सरकारी कामकाज के निष्पादन में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक (जो पेशन नहीं है) को भारतीय कर से छूट प्राप्त होगी।

3. विवादाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त कोई भी पेंशन उम संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबन्ध, दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ किये गये किसी व्यापार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में की गई अदायगी पर लागू नहीं होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "सरकार" शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की कोई राज्य सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थायी प्राधिकरण तथा विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक तथा हंगरी का राष्ट्रीय बैंक शामिल होगा।

अनुच्छेद 20

विद्यार्थी

1. किसी व्यक्ति को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था ; तथा जो उस दूसरे राज्य के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा इसी प्रकार की अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में मात्र एक विद्यार्थी की हैसियत में अथवा एक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु की हैसियत में दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है तथा उस दौर के सिलसिले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहली बार पहुंचने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ठहरता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी—

(क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विदेश से प्राप्त होने वाली सभी रकमों पर ; तथा

(ख) किसी "विगत वर्ष" अथवा "कराधेय वर्ष" के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रयोजनों के लिए उसे उपलब्ध स्रोतों की पूर्ति करने के उद्देश्य से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई व्यक्तिगत सेवाओं के लिए 20,000 रु. अथवा 75,000 फोरिन्ट्स से अधिक के किसी पारिश्रमिक पर।

2. किसी व्यक्ति को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तथा जो केवल अध्ययन, शोधकार्य अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, तथा दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षणिक अथवा धर्मार्थ संगठन से अथवा किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा निष्पन्न किसी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, उस दौर के सिलसिले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहली बार पहुंचने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार का प्राप्ताधी रहता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी—

(क) ऐसे अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार की रकम पर ;

(ख) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विदेश से प्राप्त होने वाली सभी रकमों पर ; और

(ग) किसी "विगत वर्ष" अथवा "कराधेय वर्ष" के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त 25,000 रु. अथवा 90,000 फोरिन्ट्स से अधिक का कोई पारिश्रमिक यदि ये सेवाएं उसके अध्ययन, शोधकार्य, प्रशिक्षण के सिलसिले में की जाती हैं अथवा वे उसके आनुषंगिक हैं।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा संस्था" से कोई ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा कोई शैक्षणिक अथवा शोध संस्था अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 21

प्राध्यापक, अध्यापक तथा शोधित्सु

1. कोई व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी विश्वविद्यालय के अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्था के आमंत्रण पर, किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में मूलतः अध्यापन अथवा शोधकार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, उसे उस विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए व्यक्तिगत सेवाओं से प्राप्त उसकी आय पर, बाद वाले संविदाकारी राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से 24 महीने से अधिक की अवधि के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यताप्राप्त संस्था" से ऐसी शैक्षणिक अथवा शोध संस्था अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें जहां कहीं वे उद्भूत होती हों और जिनपर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसी अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है। ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिनपर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून अलग-अलग संविदाकारी राज्य में आय के निर्धारण तथा कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस अभिसमय में उनके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो।

2. हंगरी लोक गणराज्य में उद्भूत होने वाली आय पर, जो इस अभिसमय के अनुसार है, उपपैराग्राफ 4 तथा 5 के उपबन्धों के अन्वये

रहते हुए या तो प्रत्यक्षतः अथवा कटौती करके हंगरी को एक राजराज्य में कर लगाया जाएगा और उस पर भारतीय कर नहीं लगेगा।

3. भारत में उद्भूत होने वाली आय पर, जो इस अधिसूचना के अनुसार है, उप-पराग 4 तथा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, या जो प्रत्यक्षतः अथवा कटौती करके भारतीय कर लगाया जाएगा और उस पर हंगरी का कर नहीं लगेगा।

4. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई किसी अनुच्छेद 10, 11 तथा 12 के उपबन्धों के अनुसार आय की मदें प्राप्त करना है उन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा और प्रथमोलिखित राज्य उस निवासी की आय पर उस दूसरे राज्य में प्रदत्त कर की रकम के बराबर कर की कटौती किये जाने की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती उक्त कटौती किये जाने से पहले यथा संगठित कर की रकम के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो उस दूसरे राज्य से प्राप्त आय की ऐसी मदों पर लगायी जा सकने योग्य है।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 तथा 3 के उपबन्धों के होते हुए भी, आय की ऐसी मदों को जो एक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत प्राप्ती है, उस संविदाकारी राज्य में लगाये जाने वाले कर की दर की गणना करने के लिए विषय-विषय में लिया जाना चाहिए तथा उन्हें इस प्रकार विषय-विषय में लिया जाना रहेगा।

अनुच्छेद 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक-समान परिस्थितियों तथा एक-समान शर्तों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा एक-समान शर्तों के अधीन समान कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबन्ध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को सिविल हेतु अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट, राहत, कटौतियाँ मंजूर करके उपकृत करना है जो वह अपने स्वयं के निवासियों को मंजूर करता है।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा धारक स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से अथवा तत्संबंधी किसी भी अपेक्षाओं से अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है जो प्रथमोलिखित राज्य के अन्य समान उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों और एक-समान शर्तों के अधीन लगायी जाती है अथवा लगायी जा सकती है।

4. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस अधिसूचना के विषय हैं।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है, तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा 1751 GI/86—2

पर्याप्त उपायों के होते हुए भी उक्त संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को भगना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह दावा कर निवारण की तारीख से, अथवा श्रोत पर कर को रोक जाने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, तीन वर्ष की अवधि के भीतर उन्नत किया जाये।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी समुचित हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस अधिसूचना के अनुकूल नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा, चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय-समय क्यों न हो।

3. यदि इन अधिसूचना की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के आकांक्ष के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस प्रकार में व्यवस्था नहीं की गयी है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अधिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार भी कर सकते हैं। अहाँ समझौता करने की दृष्टि से विचारों का सीधे प्राधान्य-प्रधान उपयुक्त समझा जाए तो इस प्रकार का विचार-विमर्श एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिनमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे (ऐसी सूचना तथा दस्तावेज जो संबंधित कराधान कानूनों के अन्तर्गत उनके अधिकार में हो तथा प्रशासन के सामान्य तरीके से प्राप्त की जा सके) जो इस अधिसूचना के उपबन्धों को निष्पन्न करने के लिए अथवा घोषाघड़ी के निवारण के लिए अथवा अव्यवचन अथवा करों के परिहार का निवारण करने अथवा उसका पता लगाने के लिए अथवा करों के संबंध में कानूनी परिहार के विरुद्ध सांख्यिक उपबन्धों के प्रशासन के लिए जोकि इस अधिसूचना के विषय हैं के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई किसी सूचना अथवा दस्तावेजों को गुप्त समझा जाएगा परन्तु उसे ऐसे व्यक्तियों (जिनमें कोई प्रशासन अथवा प्रशासनिक निकाय भी शामिल है) को फट किया जाएगा जो उन करों के निवारण, उनकी वसूली, प्रवर्तन और-पुनर्प्राप्त अथवा अभियोजन संबंधी कार्यों, जोकि इस अधिसूचना के विषय हैं, से संबंध हैं अथवा उससे सम्बंधित किसी घोषाघड़ी अथवा ऐसे व्यक्तियों को जिनसे सूचना अथवा दस्तावेज संबंधित हैं।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा मामलों-विशेष के संबंध में अनुरोध करने पर अथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर, ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची में सहमत होंगे, जिन्हें नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाधित डालना नहीं होगा:

(क) उन अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक पथा में हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की संपादित करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन को करना स्थिति में न हो;

हंगरी लोक गणराज्य की सरकार
के लिए

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT
OF THE HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and
the Government of the Hungarian People's Republic :

Desiring to further expand and facilitate mutual
economic relations, have resolved to conclude a
Convention for the avoidance of double taxation
with respect to taxes on income

and Have Agreed as Follows :—

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are
residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income
imposed on behalf of each Contracting State or of
its political sub-divisions or local authorities, irres-
pective of the manner in which they are levied.

2. The taxes to which this Convention shall apply
are :

- (a) In the case of India :
 - (1) income-tax including any surcharge thereon ;
 - (2) surtax ;
(hereinafter referred to as "Indian tax").
- (b) In the case of the Hungarian People's Republic :
 - (1) general income-tax (az általános jövedelemadó);
 - (2) income-tax on household and auxiliary farms (a háztáji és kiegészítő gazdaságok jövedelemadója);
 - (3) corporation taxes (a társulati adó és a társáji adó);
 - (4) special corporation tax (a társulati Kolonácé);
 - (5) profit tax of state enterprises (az állami vállalatok nyereségadója);
 - (6) town and community contribution (városi és községi hozzájárulás);
 - (7) levy on dividends and profit distributions of commercial companies (a kereskedelmi társaságok és nyereség kifizetési utáni illeték);
(hereinafter referred to as "Hungarian tax").

3. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 2 of this Article.

4. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting State shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws which are the subject of this Convention and furnish copies of relevant enactments and regulations.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the terms "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law ;
- (b) the term "Hungarian People's Republic" means the territory of the Hungarian People's Republic ;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or the Hungarian People's Republic; as the context requires ;
- (d) the term "person" comprises an individual, a company and any other body of persons ;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes ;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (g) the term "national" of a Contracting State means :
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State ;
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State ;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between the places in the other Contracting State ;
- (i) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) ; and in the case of the Hungarian People's Republic, the Ministry of Finance.

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting State, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him ; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which the centre of his vital interests is located ;
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode ;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national ;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting State shall settle the question by mutual agreement in accordance with Article 25.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business or production through which the activities of an enterprise are wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop or a warehouse ;
- (f) a mine, a quarry, an oil field or other place of extraction of natural resources ;
- (g) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities

in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character ;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person :

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph ; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, all India, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be designed as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein,

there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

4. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expense which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere as are in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State.

2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply where the enterprise has an office or agency in the other State for the transportation of goods or persons. However, this shall only apply to activities directly connected with the business of aircraft transportation.

4. Interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic as mentioned in paragraph 1 shall be regarded as income from the operation of such aircraft.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, and the dividends relate to a new contribution, the tax so charged shall not exceed fifteen per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services, from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits even if the dividends paid or the undistributed profit consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. As used in paragraph 2 of this Article, the term "new contribution" means any share capital, other than bonus shares or shares of a new company formed as a result of the amalgamation of two or more existing companies, issued after the date of entry into force of this Convention by a company which is a resident of a Contracting State, and beneficially owned by a resident of the other Contracting State.

Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest and the interest is paid in respect of a loan or debt first created after the date of entry into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,—

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State ; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State ;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :

(i) in the case of Hungarian People's Republic, the Magyar Kalkereskedelmi Bank Rt., to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only ;

(ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only ;

(iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade ;

(iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4 The term "interest" as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent

personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or a fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or the fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2 However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, provided that where the royalties or fees for technical services are paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof and they are paid in respect of a right or property which is first granted, or under a contract which is signed, after the date of entering into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed,—

(a) in the case of royalties, 40 per cent of the gross amount thereof;

(b) in the case of fees for technical services, 20 per cent of the gross amount thereof.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind including rentals received as a consideration.

(a) for the use of, or the right to use, any copy right of literary artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting

(b) for the use of, or the right to use, any patent, trade mark, design or model, plan,

secret formula or process, or any industrial commercial, or scientific equipment;

- (c) for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 14 (Independent Personal Services), in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a contracting State where the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to make the payments was incurred and the payments are borne by that permanent establishment or fixed base, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or the fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid exceed, for whatever reason the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains arising from a capital asset being ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of personal services in an independent capacity shall be taxable only in that State unless such services are performed in the other Contracting State, in which case such income may be taxed in the other Contracting State, if

- the individual is present in that other State for a period or periods aggregating more than 90 days in the 'previous year' or 'taxable year', as the case may be, or
- the individual has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much of the income as is attributable to that fixed base.

2. The term "independent personal services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the

other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant 'previous year' or 'taxable year' as the case may be, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income, may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14, and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income derived from such activities shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

4. For the purpose of this Article, the term "Government" includes a State Government, a political sub-division, or a local authority of either Contracting State.

1751 GI/86—3

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of the Republic of India to any individual who is a citizen of India in respect of services rendered in the discharge of Governmental functions in the Hungarian People's Republic shall be exempt from Hungarian tax.

2. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of the Hungarian People's Republic to any individual who is a citizen of the Hungarian People's Republic in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in India shall be exempt from Indian tax.

3. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual shall be taxable in that Contracting State.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

5. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government, a political sub-division or local authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the National Bank of Hungary.

Article 20

STUDENTS

1. An individual who is or was immediately before visiting the other Contracting State a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State solely as a student at an approved university, college, school or other similar approved institution in that other Contracting State or as a business or technical apprentice therein, for a period not exceeding five years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit shall be exempt from tax in that other Contracting State on

- (a) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance education or training; and

- (b) any remuneration not exceeding Rs. 20000 or 75000 forints, during any 'previous year' or taxable year' as the case may be, for personal services rendered in that other Contracting State with a view to supplementing the resources available to him for such purposes.

2. An individual who is or was immediately before visiting the other Contracting State a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for the purposes of study, research or training solely as a recipient of a grant, allowance or award from the Government of either of the Contracting States or from a scientific, educational or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of either of the Contracting States for a period not exceeding five years from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit shall be exempt from tax in that other Contracting State on

- (a) the amount of such grant, allowances or award;
- (b) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (c) any remuneration not exceeding Rs. 25000 or 90000 forints during any 'previous year' or 'taxable year' as the case may be, in respect of services in that other Contracting State if the services are performed in connection with his study research training or are incidental thereto.

3. For the purposes of paragraph 1, "approved university college, school or institution" means a university college school and an educational or research institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who, at the invitation of the Government of the other Contracting State or of a university or other approved institution situated in that other Contracting State, visits that other Contracting State for the primary purpose of teaching or engaging in research, or both at a university or other approved institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on his income from personal services for teaching or research at the university or the approved institution, for a period not exceeding 24 months from the date of his arrival in the latter Contracting State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an educational or research institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1. and 2, items, of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the assessment and taxation of income in the respective Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Convention.

2. The income arising within the Hungarian People's Republic which in accordance with this Convention may be subjected to tax in the Hungarian Peoples Republic either directly or by deduction, subject to the provisions of sub-paragraphs 4 and 5, shall not be subject to Indian tax.

3. The income arising within India which in accordance with this Convention may be subjected to tax in India either directly or by deduction, subject to the provisions of sub-paragraphs 4 and 5, shall not be subject to Hungarian tax.

4. Where a resident of a Contracting State derives items of income which in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in that other State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from that other State.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article, the items of income which under the laws of a Contracting State should be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State shall continue to be so taken into account.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in the that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

4. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within three years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of

double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (being information and documents which are at their disposal under the respective taxation laws and obtained in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of fraud or prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes or the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of this Convention. Any information or documents so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of taxes which are the subject of this Convention or any fraud connected therewith, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSIONS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic or consular missions under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :—

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given ;
- (b) in the Hungarian People's Republic, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

Article 29

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect :—

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given ;
- (b) in the Hungarian People's Republic, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at New Delhi this Thirtieth day of October one thousand Nine hundred and eighty six in the English language.

Sd/-

(Vishwanath Pratap Singh)
Finance Minister

For the Government of the
Republic of India.

(Dr. Istvan Hetenyi)
Finance Minister

For the Government of the
Hungarian People's Republic.

PROTOCOL

The Government of the Republic of India and the Government of the Hungarian People's Republic.

Having entered into a Convention for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income.

Have agreed, at the time of signing the said Convention, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof :

Concerning Article 5, the term permanent establishment shall be deemed not to include the use of facilities or the maintenance of a stock of goods or of merchandise solely for the purpose of storage, display or delivery of spare parts or components required by way of replacement under any warranty provisions of a contract under which any machinery or equipment is supplied by an enterprise of a Contracting State to an enterprise of the other Contracting State.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at New Delhi, this Thirtieth day of October 1986 in English Language.

Sd/-

(Vishwanath Pratap Singh)
Finance Minister

For the Government of the
Republic of India.

(Dr. Istvan Hetenyi)
Finance Minister

For the Government of the
Hungarian People's Republic
[No. 7181/F. No. 501/14/73-FTD]
V. D. ERADI, Jt. Secy.